



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 16, 2019/पौष 26, 1940
No. 17] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 16, 2019/PAUSHA 26, 1940

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 8 जनवरी, 2019

सं. टीएमपी/79/2018-विधि.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) में भारत सरकार द्वारा जारी नीति निदेश के अनुपालन में, एमओएस द्वारा अपने पत्र सं. आईडब्ल्यूटी-11/28/2018-आईडब्ल्यूटी दिनांक 26 दिसम्बर 2018 और अनुवर्ती ईमेल दिनांक 31 दिसम्बर 2018 द्वारा यथा संप्रेषित, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित “महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018” अधिसूचित करता है।

महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 का प्रासंगिक खंड विनिर्दिष्ट करता है कि प्रशुल्क नीति जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी। एमओएस ने अपने पत्र दिनांक 26 दिसम्बर 2018 द्वारा इस प्राधिकरण को निदेश जारी किया है। तदनुसार, इस महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 को 26 दिसम्बर 2018 से लागू किया गया माना जाना चाहिए।

प्रस्तावना

पत्तन सेवाओं के प्रावधान के लिए बाजार परिस्थितियों में 1996 से महापत्तनों में सार्वजनिक निजी भागीदारियों की शुरुआत का अनुसरण करते हुए पत्तन अवसंरचना के विस्तार और निजी क्षेत्र में उदारवाद से महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। गैर-महापत्तनों ने तेजी से विस्तार किया है और अब उनकी महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसके अलावा, महापत्तन न्यासों और गैर-महापत्तनों के बीच विनियमन कार्यप्रणाली में एकरूपता नहीं है। जब महापत्तन न्यासों के प्रशुल्क लागत जमा प्रतिलाभ दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए विनियमित किए जा रहे हैं, गैर-महापत्तन किसी प्रशुल्क विनियमन से आच्छादित नहीं हैं। अतः बाजार बलों को जवाब देने और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के दायरे के भीतर बेहतर कार्यनिष्पादन के लिए महापत्तन न्यासों को प्रोत्साहित करने के लिए भी महापत्तन न्यासों को अधिकार देने की जरूरत महसूस की गई थी। इस कार्य को पूरा करने के लिए, सरकार ने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 जारी की थी। चूंकि नीति की वैधता 3 वर्षों के लिए थी, इसलिए नीति की समीक्षा करने कार्य हाथ में लिया गया था और महापत्तनों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

परामर्शी प्रक्रिया के दौरान महापत्तन न्यासों से प्राप्त टिप्पणियों तथा सुझावों पर विचार करते हुए, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 जारी की गई महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 में संशोधन किया गया है। सरकार ने अपने पत्र सं. 8(1)/2014-टीएमपी दिनांक 13 जनवरी 2015 द्वारा पहले पोत परिवहन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी की गई महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2015 के अतिरिक्त निम्नलिखित महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 जारी किया है।

महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु नीति, 2018

1. प्रारंभिक

- 1.1. यह नीति महापत्तन न्यासों और महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ("टीएमपी") को, जिनपर महापत्तन न्यास अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं और ("पत्तन") पर विस्तारित किए जाते हैं, में प्रशुल्कों के निर्धारण के लिए समय-समय पर यथा संशोधित महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ("एमपीटी अधिनियम") की धारा 111 के अधीन नीति निदेश के रूप में प्रशुल्कों के निर्धारण के लिए जारी की जाती है।
- 1.2. इस निदेश को "महापत्तन न्यासों के लिए प्रशुल्क नीति, 2018 ("प्रशुल्क नीति")" कहा जाएगा।
- 1.3. यह नीति जारी किए जाने की तारीख से लागू होगी, और 1 अप्रैल 2019 से संशोधन के लिए देय महापत्तनों में प्रशुल्क के निर्धारण हेतु लागू होगी। यह 1 अप्रैल 2022 तक लागू रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा पहले समीक्षा अथवा विस्तारित नहीं किया जाता है।
- 1.4. यह नीति बीओटी/बीओटी प्रचालकों अथवा निजी क्षेत्र भागीदारी के लिए किसी अन्य व्यवस्था पर लागू नहीं होगी।
- 1.5. यह एक बृहत् नीति फ्रेमवर्क है। टीएमपी नीति फ्रेमवर्क को कार्यान्वित करने के लिए, सभी महापत्तन न्यासों के साथ विचार-विमर्श से, कार्यगत दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
- 1.6. टीएमपी, लिखित में दर्ज किए गए कारणों से, अपनी ओर से अथवा संबद्ध महापत्तन न्यास द्वारा इसके समक्ष आवेदन किए जाने पर पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के अनुमोदन, पत्तन अथवा पत्तनों के किसी समूह पर प्रशुल्क नीति के किन्हीं प्रावधानों को लागू करने में छूट प्रदान कर सकता है।

2. दरमानों का निर्धारण

- 2.1. प्रत्येक महापत्तन न्यास वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर) जोकि प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के समय तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों (वर्ष 1), (वर्ष 2) और (वर्ष 3) के अंतिम लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय के जोड़ का औसत है, और प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित निवल अचल परिसंपत्तियों एवं कार्य पूंजी तथा 31 मार्च वर्ष 3 को प्राप्त प्रगतिधीन पूंजी को शामिल करते हुए नियोजित पूंजी के 16 प्रतिशत की दर से प्रतिलालम् का मूल्यांकन करेगा।
- 2.2. वास्तविक व्यय महापत्तन न्यासों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों में यथा निर्दिष्ट कुल व्यय होगा, परन्तु निम्नलिखित समायोजन और सभी महापत्तन न्यासों के साथ विचार-विमर्श से टीएमपी द्वारा निर्णीत किए जाने वाले कोई अन्य समायोजन करने होंगे:
 - (i) संपदा संबंधित गतिविधि से संबंधित सभी व्यय अतिरिक्त होंगे।
 - (ii) ऋणों पर ब्याज अतिरिक्त होगा।
 - (iii) एकमुश्त व्ययों जैसे मजदूरी की बकाया राशियां, पेंशन/ग्रेच्युटी की बकाया राशियां, मजदूरी संशोधन आदि से किए जाने वाले एक्स-ग्रेशिया भुगतानों की बकाया राशियों का केवल 1/3रा हिस्सा और अधिवर्षिता निधियों में अंशदान का 1/3रा हिस्सा एआरआर की गणना में शामिल किया जाएगा।
 - (iv) प्रबंधन और सामान्य प्रशासन उपरिव्ययों, परन्तु प्रचालन व्यय और मूल्यहास के जोड़ के 25 प्रतिशत की सीमा तक, पर ही विचार किया जाएगा।
- 2.3. 31 मार्च वर्ष 3 को यथा मूल्यांकित एआरआर को टीएमपी द्वारा महापत्तन न्यासों को यथा संप्रेषित वर्ष 4 के लिए लागू थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के 100 प्रतिशत तक सूचकांकित किया जाएगा।
- 2.4. खंड 2.3 के अनुसार महापत्तन न्यासों द्वारा निर्धारित सूचकांकित एआरआर अधिकतम वार्षिक राजस्व अपेक्षा है जिसके आधार पर महापत्तन न्यास दरमान (एसओआर) तैयार करेंगे।
- 2.5. एसओआर तैयार करने के लिए, सुविचारित किया जाने वाला यातायात वर्ष 3 के लिए पत्तन हेतु अलग-से समग्र वास्तविक यातायात होगा।
- 2.6. उपर्युक्त खंड 2.4 के अनुसार यथा मूल्यांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा के आधार पर और खंड 2.5 के अनुसार यातायात को ध्यान में रखते हुए, महापत्तन न्यासों को यह अधिकार होगा कि वे अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर बाजार की ताकतों का मुकाबला करने के लिए दरें निर्धारित करें और प्रैक्टिस कर रहे सनदी लेखाकार/लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित सूचकांकित वार्षिक राजस्व अपेक्षा की अधिकतम सीमा के भीतर एसओआर तैयार करें।
- 2.7. दरमानों में बदलाव करते समय महापत्तन न्यासों को यह सुनिश्चित करना होगा कि दरमानों में बदलावों के परिणामस्वरूप यातायात का नुकसान नहीं हो। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी महापत्तन न्यासों के अध्यक्ष की होगी।
- 2.8. एसओआर भारत सरकार द्वारा घोषित थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परिवर्तन के 100 प्रतिशत की सीमा तक मुद्रास्फीति से वार्षिक आधार पर सूचकांकित किया जाएगा। एसओआर का ऐसा स्वतः समायोजन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा और समायोजित एसओआर प्रासंगिक वर्ष के 1 मई से आगामी वर्ष के 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।
- 2.9. दरमान टीएमपी द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित लागू होने की तारीख से लागू होगा और खंड 2.8 में यथा उल्लिखित वार्षिक सूचकांकन के अधीन 3 वर्षों के लिए वैध रहेगा। वार्षिक सूचकांकन इस प्रशुल्क नीति के खंड 3.2 के अधीन होगा।
- 2.10. केपटिव बर्थों/सुविधाओं, जहां पत्तन और संबद्ध उपयोक्ता द्वारा किए गए परस्पर करार में पृथक प्रशुल्क व्यवस्था निर्धारित की गई है, के लिए प्रशुल्क व्यवस्था तत्संबंधी व्यवस्था द्वारा शासित की जाती रहेगी। विशिष्ट करारों द्वारा कवर नहीं की गई केपटिव बर्थों/सुविधाओं हेतु प्रशुल्क टीएमपी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना जारी रहेगा।

3. महापत्तन न्यासों के कार्यनिष्पादन मानक

- 3.1. महापत्तन न्यास कंटेनर प्रहस्तन के मामले में औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, औसत फेरे प्रति घंटा के अनुसार कार्गो संबंधित सेवाओं के लिए कार्यनिष्पादन मानक भी बनाएंगे। कार्गो-वार जलयान बर्थ दिवस आउटपुट के लिए यह जरूरी नहीं है। इसके बजाय, महापत्तन न्यास समग्र औसत जलयान बर्थ दिवस आउटपुट प्रस्तावित कर सकते हैं। पोत साइड सेवाओं के लिए, पत्तन पोतों के औसत वापसी समय और पोतों के औसत प्री-बर्थिंग समय के अनुसार कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित करेगा।
- 3.2. खंड 2.8 में यथा दिया गया एसओआर का सूचकांकन महापत्तन न्यासों द्वारा पूरे किए गए कार्यनिष्पादन मानकों की उपलब्धि के अधीन होगा जैसाकि खंड 3.1 में विनिर्दिष्ट किया गया है। यदि पत्तन विशेष कार्यनिष्पादन मानक पूरे नहीं करता है तो अगले वर्ष के दौरान सूचकांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. प्रस्ताव भरने और कार्यवाही करने की प्रक्रिया

- 4.1. प्रदत्त सेवाओं अथवा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं दरमान, उनपर शासित शर्तों सहित, और कार्यनिष्पादन मानक समय-समय पर यथा संशोधित इस नीति के अनुसार, वैयक्तिक महापत्तन न्यास द्वारा तैयार किए जाएंगे।
- 4.2. महापत्तन न्यास प्रस्तावित कार्यनिष्पादन मानकों के साथ मसौदा दरमान 15 दिनों के भीतर प्रासंगिक पणधारियों/प्रयोक्ताओं की टिप्पणियों के लिए पत्तन एवं टीएएमपी का निर्दिष्ट इमेल पता देते हुए अपनी वेबसाइट पर डालेगा।
- 4.3. महापत्तन न्यास पत्तन प्रयोक्ताओं से प्राप्त टिप्पणियों पर अपने जवाब पत्तन प्रयोक्ताओं से टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से 15 दिनों के भीतर टीएएमपी को प्रस्तुत करेंगे।
- 4.4. यदि किसी प्रस्ताव अथवा मामले के लिए प्रयोक्ताओं से कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं तो टीएएमपी को कोई संयुक्त सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

5. शिकायत निवारण

यदि टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों को महापत्तन न्यास द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के संबंध में किसी उपयोक्ता की कोई शिकायत होगी तो वह टीएएमपी को अभ्यावेदन देने को वरीयता देगा जिसके बाद टीएएमपी अभ्यावेदन की जांच करेगा तथा टीएएमपी द्वारा यथा अधिसूचित कार्यनिष्पादन मानकों का अनुपालन करने के निदेश के साथ संबद्ध पत्तन न्यास को अपने निर्णय अग्रेषित करेगा।

6. महापत्तन न्यासों द्वारा अनिवार्य प्रकटन

सभी महापत्तन न्यास अपने प्रत्येक बर्थ के लिए कार्गो यातायात, जलयान बर्थ दिवस आउटपुट, जलयानों का औसत वापसी समय, औसत बर्थिंग-पूर्व प्रतीक्षा समय एवं वसूल किए गए प्रशुल्क पर वार्षिक रिपोर्ट टीएएमपी को भेजेंगे। इसके अलावा, कंटेनर बर्थों के लिए, वार्षिक रिपोर्ट कंटेनरों के लिए औसत फेरे प्रति क्रेन घंटा और औसत विराम समय पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पत्तनों द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। टीएएमपी द्वारा अपेक्षित की जाने वाली कोई अन्य सूचना भी उन्हें समय-समय पर भेजनी होगी।

7. अन्य पहलू

- 7.1. दरमानों में निर्धारित दरें अधिकतम स्तर हैं। पत्तन, यदि वे ऐसा चाहें तो, कम दरें प्रभारित कर सकते हैं। भूमि तथा भवनों के लिए दरमानों के संबंध में, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भूमि नीति दिशानिर्देशों के अधीन दरमानों के निर्धारण हेतु निर्धारित प्रावधान लागू होंगे।
- 7.2. एसओआर की अधिसूचना के बाद, पत्तन, यदि वे ऐसा चाहें तो, एसओआर में निर्धारित शर्तों को युक्तिसंगत भी बना सकेंगे।
- 7.3. पत्तनों को ऐसी कम की गई दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों को युक्तिसंगत बनाए जाने के बारे में जनता को अधिसूचित करना होगा और ऐसी कम की गई दरों और/अथवा ऐसी दरों के कार्यान्वयन को शासित करने वाली शर्तों में आगे किन्हीं और बदलावों के बारे में भी जनता को अधिसूचित करते रहना होगा बशर्तें नई निर्धारित दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक नहीं होंगी।
- 7.4. महापत्तन उन्हें उपलब्ध करवाई गई सेवाओं के लिए ही वसूली करेंगे। लेबर की कल्पित बुकिंग और अन्य समान कल्पित प्रभारों की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 7.5. रियायती प्रशुल्क, सरकार के नीति निदेशों के अनुसार, तटीय कार्गो/कंटेनरों/पोतों के लिए निर्धारित किया जाएगा।
- 7.6.1. जब कभी किसी नई सेवा/कार्गो/उपस्कर/सुविधा के लिए विशिष्ट प्रशुल्क उस पत्तन विशेष के दरमान में उपलब्ध नहीं हो तो संबद्ध महापत्तन न्यास प्रशुल्क तथा कार्यनिष्पादन मानक अंगीकृत करते हुए उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु यदि कोई किसी महापत्तन न्यास में तुलनीय कार्गो/उपस्कर/सेवा के लिए निर्धारित किया गया हो, टीएएमपी का रुख कर सकता है। यदि किसी महापत्तन न्यास में दर उपलब्ध नहीं हो तो अथवा यदि उपलब्ध दर प्रस्तावित नए कार्गो/सेवा/उपस्कर/सुविधा का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करती हो तो पत्तन 2008 दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए अथवा दरित क्षमता अथवा सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशेषता के आधार पर निर्धारित सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में उक्त नए कार्गो/उपस्कर/सेवा/सुविधा के लिए प्रशुल्क की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव दाखिल कर सकता है। यदि ऊपर निर्धारित विकल्पों के आधार पर प्रशुल्क का निर्धारण उपलब्ध नहीं हो तो पर्याप्त कारण देने के बाद महापत्तन न्यास लागत जमा 16 प्रतिशत प्रतिलाभ सूत्र के आधार पर दरों का प्रस्ताव कर सकता है।
- 7.6.2. नए कार्गो/उपस्कर/सुविधा अथवा नई सेवा के उपयोग के लिए दर की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव नए कार्गो/सुविधा अथवा नई सेवा की शुरुआत की संभावित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले टीएएमपी को अग्रेषित किया जाएगा। नए कार्गो/नई सेवा के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु, टीएएमपी यथा निर्धारित सामान्य परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।
- 7.6.3. परिचालित की जाने वाली तदर्थ दर और अंतरिम अवधि में लागू किए जाने वाले कार्यनिष्पादन मानक ऊपर खंड सं. 7.6.1 में उल्लिखित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए तथा इसपर संबद्ध उपयोक्ता(ओं) के साथ परामर्श से होनी चाहिए।

- 7.7. असाधारण परिस्थिति में, यदि महापत्तन न्यास मेजर केपिटल व्यय जैसे मेजर केपिटल निकर्षण आदि प्रोद्भूत करता है, जो एस्करो खाते, रॉयल्टी/राजस्व हिस्सेदारी अर्जनों, संपदा गतिविधि से अधिशेष और केपिटल परिसंपत्ति परिवर्तन आरक्षण, यदि कोई हो, में शेष से पूरा नहीं किया जा सकता तो यह उपलब्ध करवाई गई सीमित अवधि के लिए ऐसे पूंजी व्यय को पूरा करने के लिए विशेष लेवी के निर्धारण हेतु टीएमपी का रुख कर सकता है जैसे परियोजना के मूल्यांकन के समय परिकल्पित किया गया था और वित्तीय आंतरिक प्रतिलाभ दर (एफआईआरआर) की गणना में सुविचारित किया गया था।
- 8. अन्य प्राधिकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा वसूल किए गए प्रभारों का विनियमन**
- 8.1. ऐसे मामलों में जहां धारा 42(3) के अधीन प्राधिकृत करने की व्यवस्था बीओटी रियायत करार के माध्यम से इतर होती है तो ऐसी सेवाओं के लिए अधिकतम दरें निर्धारित की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए, इन प्रभारों के लिए प्रस्ताव हेतु प्रशुल्क विनियमन के दायरे के अधीन आने वाली ऐसी प्राधिकृत सेवाएं चिह्नित करने के बाद संबद्ध महापत्तन न्यास द्वारा शुरुआत की जाएगी और टीएमपी को अग्रेषित किया जाएगा। इस प्रस्ताव में सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित किए जाने वाले कार्यनिष्पादन मानक शामिल किए जाएंगे और कार्यनिष्पादन मानक से जुड़ा प्रशुल्क प्रस्तावित किया जाएगा।
- 8.2. यदि किसी व्यवस्था के अधीन सेवा/सुविधा विशेष के लिए संबद्ध महापत्तन में अधिकतम प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है तो पत्तन किसी अन्य महापत्तन न्यास में निर्धारित समान सेवा/सुविधा के लिए निर्धारित किया गया प्रशुल्क अंगीकृत करेगा। यदि किसी महापत्तन न्यास में प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया जाता है अथवा निर्धारित दर परिकल्पित कार्गो/सेवा/सुविधा के लिए प्रतिनिधि नहीं हो तो पत्तन न्यास 2008 के दिशानिर्देशों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए सर्वोत्तम क्षमता के संदर्भ में अथवा (सेवा/सुविधा/उपस्कर की तकनीकी विशिष्टता के संदर्भ में) दरित क्षमता के आधार पर प्रस्ताव दाखिल कर सकेगा। पत्तन न्यास के प्रस्ताव में सेवा प्रदाता द्वारा अर्जित किए जाने वाले कार्यनिष्पादन मानक शामिल किए जाएंगे और कार्यनिष्पादन मानकों से जुड़ा प्रशुल्क प्रस्तावित किया जाएगा।
- 8.3. खंड 8.1 और 8.2 के संदर्भ में टीएमपी द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क दूसरे वर्ष के आगे से इन दिशानिर्देशों के खंड 2.8 में यथा निर्धारित स्वतः सूचकांकन के अधीन होगा।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असाधारण/489/18]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 8th January, 2019

No.TAMP/79/2018-Misc.—In compliance of the policy direction issued by Government of India in the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), as conveyed by MOS vide its letter No.IWT-11/28/2018-IWT dated 26 December 2018 and subsequent e-mail dated 31 December 2018, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the following “Tariff Policy for Major Port Trust, 2018”.

The relevant clause of the Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 stipulates that the Tariff Policy will come into effect from the date of issue. The MOS has issued the direction to this Authority vide its letter dated 26 December 2018. Accordingly, this Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 should be deemed to have come into force from 26 December 2018.

PREAMBLE

The market conditions for provision of port services have undergone significant change since liberalization in the Port sector and expansion of port infrastructure following the introduction of Public Private Partnerships at Major Ports since 1996. Non-major ports have expanded rapidly and now have a substantial presence. Further, there is no parity in the regulation mechanism between the major port trusts and the non-major ports. Whilst tariffs of Major Port Trusts are regulated following cost plus return approach, non-major ports are not covered by any tariff regulation. A need was, therefore, felt to give flexibility to the Major Port Trusts to react to the market forces and also to encourage Major Port Trusts for better performance within the ambit of Major Port Trusts Act, 1963. In order to accomplish this, the Government issued Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 vide communication No.8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015. Since the validity of the Policy was for a period of 3 years, the Policy was taken up for review and consultation process was initiated with the Major Port Trusts.

Taking into consideration the comments and suggestions received from Major Port Trusts during the consultation process, the Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 issued by the Ministry of Shipping vide letter No.8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015 has been modified. The Government has issued the following Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018, in supersession of the Policy for Determination of Tariff for Major Port Trusts, 2015 issued by the Government of India in the Ministry of Shipping earlier vide its communication No.8(1)/2014-TAMP dated 13 January 2015.

TARIFF POLICY FOR MAJOR PORT TRUSTS, 2018**1. PRELIMINARY**

- 1.1. This Policy is issued to the Major Port Trusts and the Tariff Authority for Major Ports (the “TAMP”) as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 as amended from time to time (the “MPT Act”), for fixation of tariffs at Major Port Trusts to which the provisions of the MPT Act apply or are extended (the “Port(s)”).
- 1.2. The direction may be called ‘Tariff Policy for Major Port Trusts, 2018 (the “Tariff Policy”)’.
- 1.3. This Policy shall come into effect from the date of issue, and would be applicable for determination of tariff in major ports due for revision w.e.f. 1st April 2019. It shall remain in force till 1 April 2022 unless reviewed earlier or extended by the Government.
- 1.4. This Policy is not applicable to BOT / BOOT operators or any other arrangement for private sector participation.
- 1.5. This is a broad policy framework. The TAMP may, in consultation with all the Major Port Trusts, issue working guidelines, if required, to operationalise the policy framework.
- 1.6. The TAMP, for reasons to be recorded in writing, may relax with the approval of Ministry of Shipping (MOS), application of any of the provisions of the Tariff Policy to a port or a group of ports, on its own or on an application made before it by the concerned Major Port Trust.

2. DETERMINATION OF SCALE OF RATES

- 2.1. Each Major Port Trust will assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of Actual Expenditure as per the final Audited Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal, plus Return at 16% of Capital Employed comprising of Net Fixed Assets plus Working Capital plus capital work-in-progress obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.
- 2.2. Actual Expenditure will be the total expenditure as reflected in the Audited Annual Accounts of the Major Port Trusts, subject to following adjustments and any other adjustments to be decided by TAMP in consultation with all the Major Port Trusts:
 - (i) All expenses relating to Estate related activity are to be excluded.
 - (ii) Interest on loans is to be excluded.
 - (iii) Only 1/3rd of one time expenses like arrears of wages, arrears of pension/ gratuity, arrears of ex-gratia payments arising out of wage revision etc. and 1/3rd of the contribution to Superannuation Funds are to be included in the calculation of ARR.
 - (iv) Management and General Administration Overheads subject to a cap of 25% of aggregate of the operating expenditure and depreciation is only to be considered.
- 2.3. The ARR so assessed as on 31st March Y3 will be indexed by 100% of the Wholesale Price Index (WPI) applicable for the year Y4 as communicated by TAMP to the Major Port Trusts.
- 2.4. The indexed ARR determined by the Major Port Trusts as per clause 2.3 is the ceiling Annual Revenue Requirement based on which the Major Port Trusts will draw the Scale of Rates (SOR).
- 2.5. For drawing the SOR, the traffic to be considered would be the overall actual traffic exclusively for the port for Y3.
- 2.6. Based on the Annual Revenue Requirement as assessed as per Clause 2.4 above and taking into account the traffic as per Clause 2.5, the Major Port Trusts will have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on its commercial judgement and draw the SOR within the ceiling of indexed Annual Revenue Requirement, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant.
- 2.7. While going for a change in SOR the Major Port Trusts have to ensure that as a result of the changes in SOR there will not be a loss of traffic. The responsibility of ensuring this would rest with the Chairman of the Major Port Trusts.
- 2.8. The SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 100% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India. Such adjustment of SOR will be made every year and the adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.
- 2.9. The SOR will be effective from the date of effect mentioned in the Notification issued by TAMP and shall remain valid for 3 years subject to annual indexation as mentioned in clause 2.8. The annual indexation will be subject to Clause 3.2 of this Tariff Policy.

- 2.10. Tariff arrangement for captive berths/ facilities where a separate tariff arrangement is prescribed in the mutual agreement entered into by the port and the concerned user, will continue to be governed by the respective agreement. Tariff for captive berths/ facilities not covered by specific Agreements will continue to be stipulated by TAMP.

3. PERFORMANCE STANDARDS OF MAJOR PORT TRUSTS

- 3.1. The Major Port Trusts shall also commit Performance Standards for cargo related services in terms of average ship berth day output, average moves per hour in case of container handling. It is not necessary to commit cargo-wise ship berth day output. Instead, the Major Port Trusts may propose overall average ship berth day output. For vessel side services, the port shall prescribe Performance Standards in terms of average turnaround time of vessels and average pre-berthing time of vessels.
- 3.2. The indexation of SOR as provided in Clause 2.8 will be subject to achievement of Performance Standards committed by Major Port Trusts as stipulated in Clause 3.1. If a particular port does not fulfil the Performance Standard, no indexation would be allowed during the next year.

4. PROCEDURE FOR FILING AND PROCESSING THE PROPOSAL

- 4.1. The SOR, along-with conditionalities governing them, for services rendered or facilities provided and Performance Standards shall be formulated by the individual Major Port Trust, in accordance with this Policy as amended from time to time.
- 4.2. The Major Port Trusts shall host the draft SOR along with the proposed Performance Standards in its website and giving the designated email address of Port as well as TAMP for comments of relevant stakeholder/ users within 15 days' time.
- 4.3. The Major Port Trusts shall submit its replies on the comments received from Port Users to TAMP not later than 15 days from the last date of receipt of comments from the port users.
- 4.4. In case there are no objections from users for a proposal or a case, TAMP need not organize any joint hearing.

5. GRIEVANCE REDRESSAL

In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the Major Port Trust of the Performance Standards as notified by the TAMP, he may prefer a representation to TAMP which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and shall forward its findings to the concerned Port Trust with a direction to comply with the Performance Standards as notified by the TAMP.

6. MANDATORY DISCLOSURES BY MAJOR PORT TRUSTS

All the Major Port Trusts shall furnish to TAMP annual reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized for each of its berth. In addition, for the container berths, annual reports shall also be provided on average moves per crane hour and average dwell time for containers. The annual reports shall be submitted by the Ports within 60 days following the end of each of the year. Any other information which may be required by TAMP shall also be furnished to them from time to time.

7. OTHER ASPECTS

- 7.1. The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels. The ports may, if they so desire, charge lower rates. As regards Scale of Rates for Land and Buildings, the provisions prescribed for fixation of Scale of Rates under the Land Policy Guidelines issued by the Government from time to time will apply.
- 7.2. Subsequent to the Notification of SOR, the ports may also, if they so desire, rationalise the conditionalities prescribed in the SOR.
- 7.3. The ports should notify the public such lower rates and/ or rationalisation of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further changes in such lower rates and/ or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rates notified by the TAMP.
- 7.4. Major Ports shall charge only for services provided by them. No notional booking of labour and other similar notional charges would be permitted.
- 7.5. Concessional tariff will be prescribed for coastal cargoes/containers/ vessels, as per the policy directions of the Government.
- 7.6.1. Whenever a specific tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR, of that particular port, the concerned Major Port Trust can approach TAMP for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service adopting the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/

equipment/ service in any Major Port Trust. If there is no rate available in any Major Port Trust or if the rate available is not representative enough of the proposed new cargo/ service/ equipment/ facility, then the port may file the proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment. If determination of tariff based on the above prescribed options is not available, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula.

- 7.6.2. Proposal for notification of rate for use of a new cargo/ equipment/ facility or a new service shall be forwarded to the TAMP at least 60 days prior to the expected date of commissioning of the new cargo/ facility or a new service. For determination of tariff for new cargo/ new service, TAMP will follow normal consultation process as prescribed.
- 7.6.3. The ad hoc rate to be operated and the Performance Standards to be applied in the interim period must be based on the approach outlined in Clause No. 7.6.1 above and it must be in consultation with the concerned user(s).
- 7.7. In an extra-ordinary circumstance, if Major Port Trust incurs major capital expenditure like major capital dredging, etc., that cannot be met from the balance in the Escrow Account, royalty/ revenue share earnings, surplus from the estate activity and capital asset replacement reserve, if any, it may approach TAMP for fixation of a special levy to meet such capital expenditure for a limited period provided such a levy was envisaged at the time of appraisal of the project and considered in the calculation of Financial Internal Rate of Return (FIRR).

8. REGULATION OF CHARGES LEVIED BY OTHER AUTHORISED SERVICE PROVIDERS

- 8.1. In cases where authorisation arrangement u/s 42(3) is other than by way of a BOT concession agreement, ceiling rates will be prescribed for such services. For this purpose, proposals for these charges should be initiated by the concerned Major Port Trust after identifying such authorised services coming under the ambit of tariff regulation and forward to TAMP. The proposal shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standard should be proposed.
- 8.2. In case there is no ceiling tariff prescribed in the concerned Major Port for a particular service/ facility under such arrangement, the port shall adopt the tariff prescribed for the similar service/ facility prescribed in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity. [with reference to the technical specification of the service/ facility/ equipment] The proposal of Port Trust shall contain the Performance Standards to be achieved by the service provider and tariff linked to Performance Standards should be proposed.
- 8.3. The tariff approved by TAMP with reference to clauses 8.1 and 8.2 shall be subjected to automatic indexation as prescribed in clause 2.8 of these guidelines from the second year onwards.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./489/18]